CEASI TIMES

30th June 2025

HINDI

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्क्फोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क् का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- **15+ राज्य**
- **15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया**
- **20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया**
- **5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया**
- **3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया**
- **30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया**

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय करेगा झारखंड के सात जिलों में कृषि यंत्रीकरण पर सर्वेक

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची झारखंड में खेती में मशीनों के उपयोग की स्थिति जानने के लिए एक सर्वेक्षण करने जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि किसान कितनी मात्रा में कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं और सुधार की संभावनाएं कहाँ हैं।

बीएयू की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यह अध्ययन राज्य के सात जिलों – दुमका, गिरिडीह, गढ़वा, रांची, पलामू, खूंटी और गोड्डा – के 70 प्रखंडों के 70 गाँवों में किया जाएगा। इन गाँवों का चयन यादृच्छिक तरीके से किया जाएगा ताकि वास्तविक स्थिति का सही आकलन किया जा सके।

यह सर्वेक्षण राज्य में कृषि यंत्रीकरण की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आज भी अनेक किसान हंसिया, देशी हल, मुगदर और खुर्पी जैसे पारंपरिक औज़ारों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, धान की जुताई का केवल 26 प्रतिशत भाग मशीनों से किया जाता है, जबकि कटाई में मशीनों का उपयोग और भी कम है।

बीएयू के कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. डी. के. रूसिया ने बताया कि यह सर्वेक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की "सर्वभारतीय समन्वित अनुसंधान योजना - कृषि यंत्र एवं उपकरण" (एआईसीएसएफआईएम), भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। सर्वेक्षण के निष्कर्ष राज्य सरकार को भी भेजे जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि ड्रोन और मशीनरी पर अनुदान योजना

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और श्रम को कम करने के लिए कृषि ड्रोन और आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। इस पहल का उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना और उन्नत तकनीक को राज्य भर के किसानों के लिए सुलभ बनाना है। इस योजना के लिए आवेदन www.agridarshan.up.gov.in पर 12 जुलाई तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

आवेदन करने के लिए किसान पोर्टल पर जाकर "किसान कॉर्नर" अनुभाग में "यंत्र बुकिंग प्रारंभ" विकल्प पर क्लिक करें। पोर्टल पर मशीनों की जानकारी, बुकिंग की प्रक्रिया और अनुदान की पात्रता से संबंधित सभी विवरण सरल भाषा में उपलब्ध हैं। बुकिंग प्रक्रिया 27 जून से शुरू हो चुकी है।

यह योजना कृषि विभाग की "कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन" और "फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रीकरण" जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत लागू की जा रही है। इस योजना में एग्री ड्रोन, सुपर एसएमएस के साथ कंबाइन हार्वेस्टर, फार्म मशीनरी बैंक, गन्ना लगाने की मशीन, तेल निष्कर्षण इकाइयाँ, मक्का शेलर आदि पर अनुदान दिया जा रहा है। यह प्रयास खेती को सरल बनाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत मशीनों के माध्यम से अफ्रीका की खेती को बना रहा आधुनिक

भारत अफ्रीकी देशों को कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से खेती को बेहतर और आधुनिक बनाने में मदद कर रहा है। "3A" दृष्टिकोण — सस्ती (Affordable), उपयुक्त (Appropriate), और अनुकूलन योग्य (Adaptable) — के तहत भारत जिम्बाब्वे, मलावी, और लेसोथो जैसे देशों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बीज बोने की मशीनें और अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध करवा रहा है। ये मशीनें किसानों का श्रम कम करती हैं, समय बचाती हैं और फसल उत्पादन को बढ़ाती हैं।

यह सहायता आसान ऋणों और सरकारी साझेदारियों के माध्यम से दी जा रही है। भारत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र और प्रौद्योगिकी पार्क् भी स्थापित कर रहा है, जहाँ किसानों को मशीनों के उपयोग और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

बड़े यंत्रों के साथ-साथ भारत छोटे उपकरण जैसे फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र, सिंचाई प्रणालियाँ और एग्रो-ड्रोन भी उपलब्ध करा रहा है, जो छोटे किसानों के लिए उपयोगी हैं और कटाई के बाद फसल की बर्बादी को कम करते हैं। इस साझेदारी के तहत महिला किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे अफ्रीका में खेती अधिक कुशल, टिकाऊ और आधुनिक बन रही है।

आईसीएआर-सीआईएई की नई मशीन से छोटे किसानों को समय और लागत में मिलेगी राहत

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 जून को भोपाल स्थित आईसीएआर – केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (CIAE) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छोटे किसानों की ज़रूरतों के अनुसार तकनीक विकसित करने और सस्ती मशीनें सीधे खेतों तक पहुँचाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

मंत्री ने "विकसित भारत अभियान" के अंतर्गत "अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (AICRPs)" की समीक्षा की और अगले 10 वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार करने की बात कही। उन्होंने छोटे आकार की, ऊर्जा-कुशल, सेंसर-आधारित मशीनों और क्षेत्र विशेष की ज़रूरतों के अनुसार समाधान विकसित करने की बात कही। साथ ही किसान मेलों और भागीदारों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय यंत्रीकरण योजना बनाने का सुझाव भी दिया।

दौरे की प्रमुख उपलब्धि CIAE द्वारा विकसित ट्रैक्टर संचालित प्लास्टिक मल्च लेयर-कम-प्लांटर मशीन का प्रदर्शन रहा। यह मशीन एक ही बार में क्यारी बनाना, ड्रिप पाइप बिछाना और बीज बोना जैसे कार्य करती है। यह परंपरागत रूप से 29 मानव-दिवस लगने वाले कार्य को घटाकर केवल 3 मानव-दिवस में पूरा कर देती है और प्रति हेक्टेयर लगभग ₹6,600 की बचत करती है। ₹3 लाख कीमत वाली यह मशीन खीरा, तरबूज, भिंडी, स्वीट कॉर्न जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए उपयुक्त है और दो वर्षों से कम समय में अपनी लागत निकाल सकती है। यह छोटे किसानों के लिए एक लाभकारी समाधान साबित हो सकती है।

2024-25 में बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान

कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत में 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड 367.72 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.7% अधिक है। इस वर्ष बागवानी फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल में 1.81 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो अब 29.26 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। उत्पादन में यह वृद्धि मुख्यतः आलू, प्याज, हरी मिर्च, लौकी जैसे प्रमुख सब्जियों और तरबूज, आम, केला, मौसंबी और पपीता जैसे फलों की बेहतर पैदावार के कारण हुई है।

सब्जियों का उत्पादन 6.11% बढ़कर 219.67 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 207.02 मिलियन टन था। विशेष रूप से प्याज का उत्पादन लगभग 27% बढ़ने और आलू का उत्पादन 60.17 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। वहीं, फलों का उत्पादन 1.36% की मामूली वृद्धि के साथ 114.51 मिलियन टन होने का अनुमान है। बागवानी क्षेत्र में इस सुधार से खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है, जो मई 2024 में अक्टूबर 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर दर्ज की गई है।

पंजाब की गुलाब-सुगंधित लीचियों ने की वैश्विक शुरुआत, भारत के बागवानी निर्यात को नई दिशा

पठानकोट की खुशबूदार गुलाब-सुगंधित लीचियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में सफल प्रवेश कर लिया है, जहां सुजानपुर से पहली खेप दोहा (कतर) को निर्यात की गई। यह भारत के बागवानी निर्यात के लिए एक नया मील का पत्थर है। एक मीट्रिक टन प्रीमियम लीची के साथ-साथ 600 किलोग्राम अतिरिक्त लीची दुबई भेजी गई। यह पहल पठानकोट की अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों का लाभ उठाकर उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पादों को वैश्विक मंच पर ले जाने के प्रयास का हिस्सा है।

क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों द्वारा उगाई गई यह लीची अपने बेहतरीन स्वाद और खुशबू के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस लीची को पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी कीमत पर खरीदा गया और दोहा व दुबई जैसे बाजारों में ₹375 प्रति किलोग्राम तक बिक रही है। पंजाब ने 2023–24 में भारत की कुल लीची पैदावार में 71,000 मीट्रिक टन से अधिक का योगदान दिया, जो इसके तेजी से उभरते निर्यातक राज्य बनने का संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह विकास भारत की बागवानी को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है।

हॉर्टि-कोन्नेक्ट भारत2025: बागवानी क्षेत्र में नवाचार और विकास को देगा नई दिशा

भारत का प्रमुख बागवानी प्रदर्शनी आयोजन, HortiConnect India 2025, 25 से 27 सितंबर 2025 तक बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र (BIEC) में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संरक्षित खेती, सटीक कृषि, IoT, स्मार्ट सिंचाई, पुष्पकृषि और अन्य तकनीकों से जुड़ी 250 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां भाग लेंगी। इसमें 10,000 से अधिक बागवानी विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सहयोग के अनेक अवसर मिलेंगे।

कार्यक्रम में विशेष B2B बैठकें, तकनीकी प्रदर्शन और विशेषज्ञों द्वारा संचालित कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित टिकाऊ और व्यावसायिक समाधान प्रस्तुत करेंगी। प्रतिभागियों को वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों से सीधे जुड़ने, नवीन तकनीकों को जानने और रणनीतिक साझेदारियां स्थापित करने का अवसर मिलेगा। HortiConnect India 2025 भारत के बागवानी क्षेत्र में नवाचार और वृद्धि को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण मंच बनने जा रहा है।

त्रिपुरा में 'क्वीन अनानास' की खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹132 करोड़ की योजना शुरू

त्रिपुरा सरकार ने राज्य के राजकीय फल क्वीन अनानास की खेती को प्रोत्साहन देने और बाजार विस्तार के लिए ₹132 करोड़ की परियोजना की घोषणा की है। सुनहरे पीले रंग और विशिष्ट खुशबू वाले इस अनानास की खेती त्रिपुरा के पहाड़ी और आर्द्र जलवायु में न्यूनतम रासायनिक उपयोग के साथ होती है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन में सुधार करने और राज्य को उष्णकटिबंधीय फलों के बाजार में मजबूत स्थान दिलाने के उद्देश्य से की गई है।

फिलहाल राज्य में कुल 58,491 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न फलों की खेती हो रही है, जिसमें से 11,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अनानास की खेती होती है। क्वीन अनानास को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिल चुका है, जो इसकी विशेष गुणवत्ता और क्षेत्रीय पहचान को दर्शाता है। यह परियोजना त्रिपुरा के अनानास की ब्रांडिंग और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देकर राज्य को प्रीमियम अनानास उत्पादन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

डेयरी और चारा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेपियर घास योजना प्रयागराज पहु

पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और साल भर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले में अपनी हाइब्रिड नेपियर घास योजना का विस्तार कर रहा है। इस पहल से किसानों को हाइब्रिड नेपियर रूट कटिंग के साथ प्रति हेक्टेयर ₹20,000 की सब्सिडी मिलती है। एक बाय-बैक व्यवस्था भी शामिल है, जहां सरकार अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए उपज को बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत पर खरीदेगी। प्रोटीन से भरपूर और डेयरी पशुओं के लिए आदर्श नेपियर घास 20-25 दिनों में पक जाती है और प्रति एकड़ 300-400 क्विंटल उपज देती है। इसकी कम उत्पादन लागत—केवल ₹0.50 प्रति किलोग्राम—इसे हरे चारे के लिए एक टिकाऊ, उच्च-लाभ वाला विकल्प बनाती है। एक बार लगाए जाने के बाद, घास फिर से उग आती है और 10 साल तक उत्पादक रहती है हमीरपुर और बहराइच में पहले से ही चल रही इस योजना से अब प्रयागराज के किसानों को लाभ मिलने वाला है, जिसमें पहले 10 लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। अधिकारी इसे "एक-एक करके समृद्धि के बीज बोने" के रूप में वर्णित करते हैं।

एनडीडीबी ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में तीन डेयरी संयंत्रों का कार्यभार संभाला

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने 25 जून, 2025 को उत्तर प्रदेश सहकारी डेयरी संघ (PCDF) के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के बाद कानपुर, कन्नौज और गोरखपुर में तीन प्रमुख डेयरी संयंत्रों के संचालन का जिम्मा संभाल लिया है। इसके अतिरिक्त, अंबेडकर नगर में एक पशु चारा उत्पादन सुविधा का प्रबंधन भी NDDB द्वारा किया जाएगा। इस सहयोग का उद्देश्य कुशल प्रबंधन, पारदर्शिता और किसान-केंद्रित संचालन सुनिश्चित करके राज्य के डेयरी बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और पेशेवरीकरण करना है। NDDB की भागीदारी से प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने, दूध की गुणवत्ता बढ़ाने और बाजार संबंधों में सुधार की उम्मीद है। यूपी सरकार ने कहा कि समय पर भुगतान, बेहतर दूध की कीमतें और स्थिर विपणन समर्थन से डेयरी किसानों को सीधे लाभ होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक टिकाऊ होगी। NDDB की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ, इस पहल से उत्पादकता बढ़ाने, पशुधन के स्वास्थ्य का समर्थन करने और क्षेत्र में लाभप्रदता बढ़ाने की उम्मीद है। यह कदम उत्तर प्रदेश में एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग्रामीण डेयरी को मजबूत करना: पंजाब ने हजारों दुधारू पशुओं का बीमा कराया

पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और साल भर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले में अपनी हाइब्रिड नेपियर घास योजना का विस्तार कर रहा है। इस पहल से किसानों को हाइब्रिड नेपियर रूट कटिंग के साथ प्रति हेक्टेयर ₹20,000 की सब्सिडी मिलती है। एक बाय-बैक व्यवस्था भी शामिल है, जहां सरकार अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए उपज को बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत पर खरीदेगी। प्रोटीन से भरपूर और डेयरी पशुओं के लिए आदर्श नेपियर घास 20-25 दिनों में पक जाती है और प्रति एकड़ 300-400 क्विंटल उपज देती है। इसकी कम उत्पादन लागत—केवल ₹0.50 प्रति किलोग्राम—इसे हरे चारे के लिए एक टिकाऊ, उच्च-लाभ वाला विकल्प बनाती है। एक बार लगाए जाने के बाद, घास फिर से उग आती है और 10 साल तक उत्पादक रहती है हमीरपुर और बहराइच में पहले से ही चल रही इस योजना से अब प्रयागराज के किसानों को लाभ मिलने वाला है, जिसमें पहले 10 लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। अधिकारी इसे "एक-एक करके समृद्धि के बीज बोने" के रूप में वर्णित करते हैं।

बिहार ने भैंस आधारित डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की

बिहार ने डेयरी फार्मिंग और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए समग्र भैंस पालन योजना 2025-26 शुरू की है। यह योजना किसानों और बेरोजगार युवाओं को मुर्रा, जाफराबादी और भदावरी जैसी उच्च उपज देने वाली भैंसों की नस्लों के साथ डेयरी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र लाभार्थी एक या दो दूध देने वाली भैंसों के साथ इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं और अपनी सामाजिक श्रेणी के आधार पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को ₹1,21,000 की लागत वाली एक भैंस इकाई पर ₹90,750 की सब्सिडी मिलेगी। सामान्य और ओबीसी श्रेणियों के लिए, सब्सिडी राशि ₹60,500 प्रति इकाई है। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित भैंस डेयरी को बढ़ावा देकर दूध उत्पादन को बढ़ाना और ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना है। इसे सभी जिलों में संबंधित जिला पशुपालन अधिकारियों (DAHO) के माध्यम से लागू किया जाएगा। केवल पूर्ण और त्रुटि रहित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, और योग्यता प्राप्त करने के लिए भैंसें स्वीकृत नस्लों की होनी चाहिए। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

"असम में पशुपालन और पोल्ट्री विकास – आगे की राह" पर खुली चर्चा

"अमृत काल" के दौरान आत्मनिर्भर और समृद्ध असम के लिए 25-वर्षीय रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से, 9 जून 2025 को "असम में पशुपालन और पोल्ट्री विकास – आगे की राह" विषय पर एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन असम कृषि विश्वविद्यालय (AAU), खानापारा के वेटरिनरी विस्तार शिक्षा निदेशालय द्वारा, विस्तार शिक्षा संस्थान (पूर्वोत्तर), AAU, खानापारा के सहयोग से किया गया। यह कार्यक्रम EEI (NE) के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें शोधकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, विस्तार अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि, इनपुट प्रदाता और पशुपालक उद्यमी शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ. हिरण्य कुमार भट्टाचार्य (सह-निदेशक, विस्तार शिक्षा - वेटरिनरी, AAU) ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के उद्देश्यों को साझा किया। उद्घाटन सत्र में असम वेटरिनरी काउंसिल (AVC) के अध्यक्ष डॉ. डांडेश्वर डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने विशेषज्ञों को एक साझा मंच देने के इस प्रयास की सराहना की। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री लोकेन दास ने स्थानीय नस्लों के संरक्षण, घरेलू फार्मिंग मॉडल्स के विकास, पशु बीमा व क्रेडिट गारंटी योजनाओं को बढ़ावा देने और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक, पर्यावरणीय और रोजगार वृद्धि की संभावनाओं पर बल दिया।

डॉ. प्रभोध बोरा (निदेशक, अनुसंधान - वेटरिनरी, AAU) ने असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और पोल्ट्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और सहयोगात्मक प्रयासों के ज़रिए व्यावसायिक खेती के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ज़ोर दिया। डॉ. राजुमणि बोरदोलोई (निदेशक, EEI-NE) ने विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और टीम भावना से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

खुली चर्चा का संचालन अनुसंधान निदेशक (वेटरिनरी) ने किया और AVC अध्यक्ष ने सह-अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। चर्चा की शुरुआत ADEE (वेटरिनरी) ने की। इस सत्र में पशुपालन और डेयरी विभाग, असम पशुपालन एवं पोल्ट्री निगम, निजी कंपनियों, वेटरिनरी वैज्ञानिकों और उद्यमियों सहित कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।

चर्चा के दौरान असम के पशुपालन और पोल्ट्री क्षेत्र से संबंधित प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई और उनका विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर सतत विकास के लिए एक या दो मॉडल रूपरेखाएं तैयार की गईं, जिन्हें मौजूदा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत या नई नीतियों के प्रस्ताव के रूप में लागू किया जा सकता है।

एनएसओ ने कृषि और सहायक क्षेत्रों के उत्पादन पर रिपोर्ट जारी की (2011–2024)

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने "कृषि और सहायक क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट (2011-12 से 2023-24)" जारी की है। रिपोर्ट में फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्रों में मजबूती से हुई वृद्धि को दर्शाया गया है।

चालू कीमतों पर कृषि क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (GVA) 225% बढ़ा, जबकि स्थिर कीमतों पर सकल उत्पादन मूल्य (GVO) में 54.6% की वृद्धि हुई। फसल क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा, जिसमें अनाज और फल-सब्जियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही।

सब्जियों में आलू और फलों में केले का योगदान सबसे ज्यादा रहा। पशुपालन क्षेत्र में मांस उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ी है और उत्पादन लगभग दोगुना हुआ। पुष्पकृषि में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

मत्स्य क्षेत्र का GVO में हिस्सा 7% तक बढ़ा, जिसमें समुद्री मछली की भागीदारी बढ़ी है। रिपोर्ट में राज्यों की भूमिका में भी बदलाव दिखा है, जो क्षेत्रीय कृषि विकास को दर्शाता है।

पूरी रिपोर्ट https://mospi.gov.in पर उपलब्ध है।

महाराष्ट्र ने कृषि के लिए भारत की पहली एआई नीति शुरू की

तकनीक आधारित खेती की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाएग्री-एआई नीति 2025–2029 को मंजूरी दी है। ₹500 करोड़ की शुरुआती राशि के साथ यह नीति कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन, रोबोटिक्स और एडवांस्ड एनालिटिक्स के ज़रिए कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

नीति के तहत रीयल-टाइम सलाह सिस्टम, सटीक खेती के उपकरण, और ब्लॉकचेन आधारित ट्रैसेबिलिटी जैसे नवाचार शामिल हैं, खासकर अंगूर, केला और अनार जैसी निर्यात फसलों के लिए। विस्तार (VISTAAR) प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई भाषाओं में एआई आधारित सलाह किसानों को मिलेगी।

राज्य में एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज (ADeX), एआई सैंडबॉक्स, और जिओस्पेशियल इंजन जैसे डिजिटल अवसंरचना तैयार किए जाएंगे। स्टार्टअप, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह नीति महाराष्ट्र को स्मार्ट, सतत और किसान-केंद्रित कृषि का अग्रणी राज्य बनाएगी।

बिहार में पुसा स्थित BISA को बनाया जाएगा क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर हब

पुसा (समस्तीपुर): बिहार सरकार पुसा स्थित बोरलॉग संस्थान फॉर साउथ एशिया (BISA) को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की जलवायु के अनुसार दालें, तिलहन और पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत एक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जो खेती को नवाचार, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता के साथ आगे बढ़ाएगा।

प्रमुख रणनीतियों में फसल रोग और कीट प्रकोप की पूर्व चेतावनी के लिए एआई-आधारित तकनीकों का उपयोग, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना, तथा जल और मृदा संरक्षण पर विशेष ध्यान देना शामिल है। राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के आपसी सहयोग से किसानों तक इन प्रयासों का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही, कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवाचार आधारित, व्यावसायिक मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे किसानों की लागत घटे और आय में वृद्धि हो सके।

मदुरै में आयोजित एफपीओ कॉन्क्लेव में जैविक खेती को बढ़ावा और किसानों को वित्तीय सहायता देने पर जोर

मदुरै: किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) कॉन्क्लेव मदुरै में आयोजित किया गया, जिसमें तमिलनाडु के विभिन्न जिलों से 600 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत कृषि के लिए सहयोग, जागरूकता और वित्तीय समावेशन के माध्यम से एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था। प्रमुख संस्थाओं और कृषि व्यवसायों के सहयोग से आयोजित इस आयोजन में जैविक उत्पादन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

कार्यक्रम में एफपीओ को कृषि परिवर्तन के मजबूत स्तंभ के रूप में रेखांकित किया गया और किसानों के सामूहिक प्रयासों से जैविक खेती की दिशा में बदलाव को बढ़ावा देने की बात कही गई। कॉन्क्लेव में किसानों के लिए एक सह-ब्रांडेड कार्ड की शुरुआत की गई, जिससे वे जैविक इनपुट विशेष रियायती दरों पर खरीद सकेंगे। इसके साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उदार वित्तीय सहायता देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) भी किया गया।

जियवाड़ा ग्रामीण में सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट-रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा

20 जून 2025 को सीईएएसआई (CEASI) ने सोमपो जनरल इंश्योरेंस (Sompo General Insurance) के सहयोग से नुन्ना गांव, विजयवाड़ा ग्रामीण, आंध्र प्रदेश में सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट-रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर एक दिवसीय अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया।

यह प्रोग्राम किसानों को सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेज़ और क्लाइमेट-रिलेटेड रिस्क्स से निपटने की जानकारी देने की एक श्रृंखला की शुरुआत था। इस सेशन में 50 से अधिक किसान शामिल हुए, जहां सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, वॉटर कंज़र्वेशन, क्लाइमेंट-रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज़, और इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण क्रॉप इंश्योरेंस पर दिया गया जोर था। सोमपो जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों ने किसानों को बताया कि वे एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण होने वाले क्रॉप लॉस से अपनी आजीविका कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और साथ ही उन्होंने बीमा योजनाओं और एनरोलमेंट प्रोसेस की जानकारी भी दी।

यह प्रोग्राम इंटरऐक्टिव, जानकारीपूर्ण और किसानों द्वारा सराहा गया। यह CEASI और सोमपो जनरल इंश्योरेंस की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वे ग्रामीण समुदायों को अवेयरनेस, एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से सशक्त बनाना चाहते हैं।

प्रोग्राम के अंत में सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए।

यह पहल भविष्य में ऐसे और प्रयासों की नींव रखती है, जो किसानों को सशक्त बनाएंगे और लॉन्ग-टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देंगे।

अयोध्या में फार्मर्स को एमपावर करना: सस्टेनेबल शुगरकेन कल्टीवेशन को बढ़ावा

सश्वत मिठास इनिशिएटिव के तहत, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया द्वारा UPL SAS लिमिटेड के साथ साझेदारी में सस्टेनेबल शुगरकेन फार्मिंग प्रैक्टिसेज़ को अयोध्या में प्रमोट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य फार्मर्स की क्षमता को ईको-फ्रेंडली कल्टीवेशन मेथड्स के माध्यम से बढ़ाना है, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हुए एनवायर्नमेंटल रिसोर्सेज़ को भी प्रिज़र्व करें।

एक डेडिकेटेड टीम मौजूदा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ को समझने और इंप्रूवमेंट के ऑपर्च्युनिटीज़ को पहचानने के लिए एक्स्टेंसिव फील्ड सर्वे कर रही है। प्रैक्टिकल लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए, डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट्स ग्रासरूट लेवल पर बनाए जा रहे हैं। ये प्लॉट्स सस्टेनेबल शुगरकेन कल्टीवेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ दिखाते हैं, जैसे एफिशिएंट वॉटर मैनेजमेंट, सॉयल हेल्थ रेस्टोरेशन, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग।

नॉलेज डिसेमिनेशन को प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के साथ जोड़कर, यह प्रोजेक्ट फार्मर्स को क्लाइमेट-रेजिलिएंट और एनवायर्नमेंटली रिस्पॉन्सिबल एप्रोच अपनाने के लिए मोटिवेट करता है। इस इनिशिएटिव का लक्ष्य केवल क्रॉप यील्ड बढ़ाना नहीं है, बल्कि लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी और रीजन के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में इकोलॉजिकल बैलेंस सुनिश्चित करना भी है।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india